है और समिति से अपनी रिपोर्ट एक महीने में देने को कहा जाता है, तो कोई आसमान गिरने वाला नहीं है। इस प्रकार की अनेक परम्पराएं हैं जबकि सदन ने एक विशेष विधेयक को-एक महत्वपूर्ण और अविलम्बनीय विधेयक को उसमें सुधार लाने के लिए संयुक्त समिति को सौंपा, जबकि विधेयक के सिद्धान्तों को सदन में स्वीकार कर लिया था। विधेयक के मूल सिद्धान्तों की सभी ने सराहना की है। लेकिन इसमें और सुधार लाये जाने की आवश्यकता है? इसे और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है इसकी कमजोरियां और असंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है।

अतः इस विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाना चाहिये और समिति से यह अनुरोध किया जाना चाहिये कि वह अपनी रिपोर्ट एक महीने के अन्दर दे दे, ताकि सदन इसे कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ स्वीकार कर ले। विधेयक की संयुक्त समिति को भेजे जाने के बारे में एक प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अपराह्न 3.58 बजे

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य
जम्मू और कश्मीर में विकास कार्य

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब मैं माननीय प्रधान मंत्री को वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करता हूं।

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : कश्मीर में विकास कार्यों के बारे में मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं। जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है कि कश्मीर में उग्रवाद को बढ़ावा देने में युवकों में व्याप्त भारी बेरोजगारी का हाथ रहा है। इसी प्रकार राज्य में विद्युत की कमी है जोकि उद्योग तथा पर्यटन के विकास हेतु एक आवश्यक आधार है। इसलिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू करने तथा चालू परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का विचार है।

सरकार ऊधमपुर से बारामूला तक की 290 कि.मी. रेल लाइन का रेल योजना के बाहर भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में निर्माण करेगी। परियोजना पर 2500 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है तथा यह कश्मीर को शेष भारत के साथ जोड़ने में सहायक सिद्ध होगी इसके पूरा होने यह राज्य में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के अलावा रेल संपर्क राज्य के लोगों को रोजगार शिक्षा, व्यापार, आदि हेतु देश के अन्य भागों में आवागमन में यह परियोजना में सहायक होगी। ऊधमपुर से बनिहाल का सर्वेक्षण कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है तथा बारामूला तक सर्वेक्षण कार्य मार्च, 1997 तक पूरा हो जाएगा। यह लाइन कटरा-रियासी-बनिहाल-काजीगंद-श्रीनगर से होकर जाएगी।

अपराह्न 4.00 बजे

चार वर्षों में पूरा होने वाले ऊधमपुर-कटरा खंड के निर्माण कार्य को रेलवे तुरंत प्रारंभ करेगी। सरकार इस कार्य हेतु 200 करोड़ रुपए उपलब्ध करायेगी। पर्याप्त धनराशि से बारामुला तक की सम्पूर्ण रेल लाइन 8-10 वर्षों में पूरी हो सकेगी।

मुगल रोड

जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच एकमात्र कड़ी रूप जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय भूस्खलन तथा हिमपात के परिणामस्वरूप अवरूद्ध, की समस्या से ग्रस्त रहता है। राज्य के दोनों क्षेत्रों के बीच वैकल्पिक कड़ी के रूप में "आर्थिक महत्व की सड़कें" केन्द्रीय-प्रायोजित योजना के अंतर्गत सरकार मुगल रोड़ परियोजना को प्रारंभ करेगी। 85 कि.मी. लंबी इस परियोजना पर 77.40 करोड़ रुपये (1994-95 की लागत) खर्च होने का अनुमान है। परियोजना लागत केन्द्र और राज्य द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की जाएगी। जम्मू से श्रीनगर-बरास्ता राजौरी-शोपीयां तथा पुलवामा को जोड़ने वाली और छह वर्ष में पूरा होने वाला तथा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों से गुजरने वाला मार्ग पर्याप्त रूप से रोजगार अवसरों का सृजन करेगा। पूरा होने पर यह मार्ग आर्थिक क्रियाकलापों के सृजन के अलावा कश्मीर के लोगों से अलगाववादको भावना को दूर करने में मदद करेगा। तीव्र क्रियान्वयन हेतु इसे सीमा सड़क संगठन को सौंपा जाएगा।

माननीय सदस्यों को विदित है कि फ्रेंच सिविल कंट्रेक्टरों के हटने से दुलहास्ती पनबिजली परियोजना (3x130 मेघावाट) का कार्य 1992 में रुक गया था। जुलाई, 1995 में फ्रेंच कंपनी के साथ समझौते में संशोधन किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप जबकि मशीनें फ्रेंच कंपनी द्वारा भेजी जा रही हैं। शेष कार्य अन्य ठेकेदारों द्वारा किया जा सकता है। शेष कार्य हेतु निविदाएं मंगवा ली गई हैं और जांच की गई है तथा ठेका देने हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की संभावना है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि सिविल कार्य शीघ्र शुरू किए जाएं और शेष कार्य हेतु सरकारी सहायता और बाजार ऋणों समेत विभिन्न स्रोतों से धन जुटाया जाए।

माननीय सदस्यों को विदित है कि राज्य में उरी पनबिजली परियोजना (4x120 मे.वा.) नामक एक अन्य प्रमुख पन-बिजली परियोजना निर्माणाधीन है। निर्धारित समयनुसार, इस पर कार्य चल रहा है तथा पहले चरण का कार्य दिसम्बर, 1996 में शुरू होने की संभावना है। इससे विद्युत की कमी वाले इस राज्य को राहत मिलेगी।

मैंने पहले ही इस सभा में आश्वासन दिया है कि राज्य में शीघ्र ही चुनाव होने जा रहे हैं। मेरे विचार से एक या दो दिन के भीतर चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। इसीलिए मैं...यह...वक्तव्य दे रहा हूं। जब मैं वहां गया था लगभग सभी राजनीतिक दलों ने वहां इन कार्यों को करने पर बल दिया था। अतः सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि इनमें से कुछ कार्य चालू वर्ष में ही प्रारंभ किए जाएं।